

Title: Regarding resentment among the officers of the Armed Forces due to non-payment of salaries during their training programmes.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आजादी के छः दशक बाद भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के साथ जो दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारी और सिविल सेवाओं के अधिकारी, इन दोनों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। संघ लोक सेवा जब उनका चयन करता है, तो इन दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बराबर रहती है। लेकिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी जो अपनी ट्रेनिंग के लिए आईएमए, आर्मी के लोग आईएमए में, नेवी के लोग नेवल अकादमी कोल्लीकोड में और एयरफोर्स के लोग एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में जाते हैं। उनको पहले दिन से वेतन नहीं दिया जाता है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा और अन्य सेवाओं के अधिकारियों के उनके प्रशिक्षण के पहले दिन से ही वेतन दिया जाता है।

यह परिपाटी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है और यह अब तक चल रही है। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान हर वर्ष कम से कम दस-बारह लोग बोर्ड आउट किए जाते हैं। वे विकलांग हो जाते हैं। उनकी विकलांगता के कारण उनको बाहर किया जाता है। उस दशा में उनको पहले दिन से वेतन न मिलने के कारण अपनी आजीविका के लिए कहीं और आश्रय ढूंढना पड़ता है। इसलिए पहले दिन से, मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, और आप के माध्यम से सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों के साथ जो विसंगति की जा रही है, उनको अभी चार-पांच वर्ष से स्टाइपेन्ड दिया जा रहा है उसके पहले उन्हें वह भी नहीं मिल रहा था। प्रशिक्षण के दौरान उनको पहले दिन से जैसा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा के और अन्य सेवाओं के लोगों को पहले दिन से वेतन दिया जाता है वैसा ही वेतन देने का प्रावधान भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों के साथ भी किया जाए। आज भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी है। करीब 15 हजार ऑफिसर कम हैं। इसके कारण जो दूसरा दुष्परिणाम सामने आता है वह यह है कि भारतीय सशस्त्र सेना के ऑफिसर ट्रेनिंग के बाद, एक साथ ट्रेनिंग शुरू होती है और एक ही समय दो अलग-अलग अकादमी में, तो भारतीय सशस्त्र सेना के ऑफिसर ट्रेनिंग के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से एक साल जुनियर हो जाते हैं। इस विसंगति को दूर किया जाना आवश्यक है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस विसंगति को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

Arjun Ram Meghwal